

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस अपील नं०-24/2018

निरमनी माँझी वगै०

बनाम्

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा

—: आदेश :—

दिनांक

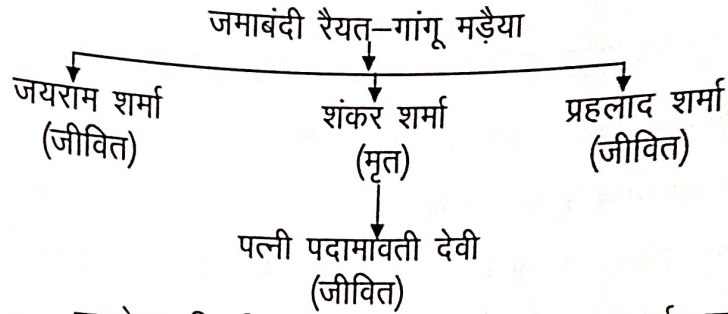
वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया निरमनी माँझी वो विशेश्वर माँझी वो दिगम्बर माँझी, पेसरान-गोतम माँझी, सा०-बसंतपुर, थाना-पोड़ैयाहाट, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के विविध वाद सं०-02/18-19 (कौशल्या देवी वो निरमनी माँझी वगै० बनाम् जयराम मिस्त्री वगै०) आदेश दिनांक-24.05.18 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्तागण का आवेदन है कि मौजा-माली नं०-27 जमाबंदी सं०-9 के अंदर दाग नं०-85 कुल रकवा 00-16-00 धुर जमीन अपीलकर्तागण के पूर्वज विशु माँझी को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रैयती उच्छेदी केश नं०-2517/34-35 के द्वारा वर्ष 1936 ई० में प्राप्त हुआ है। अपीलकर्तागण के पूर्वज से लेकर आजतक अपीलकर्तागण उक्त जमीन पर दखलकार है एवं जोत आबाद कर रहे हैं। अपीलकर्तागण का उक्त जमीन अडाणी पावर प्लांट के विकास के लिए सरकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त जमीन का क्षतिपूर्ति राशि अपीलकर्तागण को प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने विविध वाद सं०-02/18-19 आदेश दिनांक-24.05.18 के द्वारा अपीलकर्तागण के दावा को खारिज किया है, जो बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। अपीलकर्तागण ने मौजा-माली नं०-27 जमाबंदी सं०-9 दाग नं०-85 कुल रकवा 00-16-00 धुर जमीन का मुआवजा राशि अपीलकर्तागण को दिलाने के लिए अनुरोध किया है।

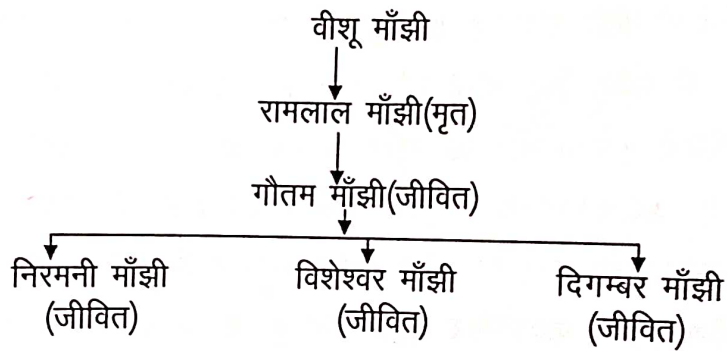
इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक-522/रा० दिनांक-13.09.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा-माली थाना नं०-27 जमाबंदी नं०-9 रैयत गांगू मड़ैया वल्द लवी मड़ैया कौम बढ़ई शा० बसंतपुर कुल रकवा

2

09-13-18 धुर जमीन सर्वे खाता खतियान के पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी नं०-9 के दाग नं०-85 के रकवा 01-06-18 धुर के अंश रकवा (16 कट्ठा) जमीन विवादित है। खतियानी रैयत के वंशावली निम्न प्रकार बतलाया गया :-



उपरोक्त विवादित दाग नं०-85 के अंदर आर०ई०आर० केश नं०-2517/34-35 आदेश दिनांक-30.05.36 के द्वारा वीशू माँझी शा० बसंतपुर को दखल कब्जा दिलाया गया है। वीशू माँझी के वंशवृक्ष निम्नलिखित बतलाया गया :-



अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा आगे प्रतिवेदित किया गया है कि उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि उक्त दाग नं० के आंशिक भाग (16 कट्ठा) जमीन पर वीशू माँझी के वंशज पोता गौतम माँझी का दखल एवं जोत करते आ रहे हैं। उक्त जमाबंदी नं०-9 दाग नं०-85 से संबंधित मामला Court of principle Dist. Judge cum Land Acquisition-Rehabilitation and Resettlement Authority, Dumka Suit No. LA 48 of 2018 कौशलया देवी व निरमनी माँझी वगै० बनाम् जयराम मिस्त्री वगै० से चल रहा है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मतव्य है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा-माली नं०-27 जमाबंदी सं०-9 दाग नं०-85 रकवा 01-06-18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गांगू मड़ैया वल्द लाबी मड़ैया के नाम से दर्ज है। उक्त

(18)

जमीन को अडानी पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित किया गया है। अपीलकर्तागण का दावा आर0ई0आर0 केश नं0-2517/34-35 आदेश दिनांक-30.05.1936 के आधार पर है। जिसका सत्यापन आवश्यक है। उनका आगे मंतव्य है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उसी जमीन का विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-भू-अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में सूट नं0-एल0ए0 48/18 लंबित है। इसलिए अपीलकर्तागण का आवेदन चलने योग्य नहीं है और खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं विज्ञ सहायक सरकारी वकील के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि मौजा-माली नं0-27 जमाबंदी सं0-9 कुल रकवा 09-13-18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गांगू मड़ैया वल्द लवी मड़ैया के नाम से दर्ज है। अपीलकर्तागण ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0-85 रकवा 00-16-00 धुर जमीन आर0ई0आर0 केश नं0-2517/34-35 आदेश दिनांक-30.05.1936 के द्वारा प्राप्त करने का दावा किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड़डा ने उच्छेदी से प्राप्ति के दावा के आधार पर अपीलकर्तागण के मुआवजा भुगतान के दावा को खारिज किया है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उसी जमीन से संबंधित मामला विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-भू-अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार उक्त आदेश से मामला प्रभावित होगा। अतः इस न्यायालय में इस स्तर पर कोई निर्णय देना अपरिपक्व होगा। मामला विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-भू-अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में लंबित मानते हुए प्रक्रिया समाप्त की जाती है। विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-भू-अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में निर्णय होने के बाद अपीलकर्ता चाहे तो पुनः वाद वापसी का आवेदन देकर वाद प्रारम्भ करा सकते हैं। आदेश की प्रति विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-भू-अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका को भेजा जाय।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड़डा।


25/8/2021
उपायुक्त,
गोड़डा।

Seen
25/8/2021